ठाकुर गोकलचंद

बनाम

परवीन कुमार

[सैयद फजल अली और विवियन बोस जे. जे।]

पंजाब की प्रथा-व्यवहार में पालन किए जाने वाले सिद्धांत प्रथागत कानून में कहा गया है-वैध प्रथा की अनिवार्यता। होशियारपुर (पंजाब) जिले की तहसील गढ़शंकर से संबंधित एक राजपूत वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ उन संपत्तियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जो एक मृत गोरखा महिला आर की थीं और जिन्हें उसने एक अजनबी से उपहार के रूप में अर्जित किया था, यह आरोप लगाते हुए कि वह आर का कानूनी रूप से विवाहित पति था और उत्तराधिकार के संबंध में पक्षों पर लागू होने वाली प्रथा के अनुसार वह आर की चल और अचल संपत्तियों का उत्तराधिकारी होने का हकदार था, प्रतिवादी की वरीयता में जो आर द्वारा उसकी बेटी थी, कि भले ही यह माना जाए कि आर का कानूनी रूप से वादी से विवाह हुआ था, यह तय किया जाने वाला सवाल होगा कि क्या संपत्ति का उत्तराधिकार जो आर को एक अजनबी से उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था और जो ऐसा विवाह, जिस पर वादी द्वारा अनुबंधित होने का आरोप लगाया गया था, स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ घटना का कार्य होने के कारण, वादी द्वारा स्थापित उत्तराधिकार के नियम को लंबे समय तक उपयोग से अपना बल प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जा सकता है और वादी किसी भी तरह से सफल होने का हकदार नहीं था।

उनके अधिपत्यों ने सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित किया जिन्हें प्रथागत कानून के प्रश्नों से निपटने में निम्नानुसार ध्यान में रखा जाना चाहिएः

वादी द्वारा अनुबंधित होने का आरोप लगाया गया था, स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ घटना का कार्य होने के कारण, वादी द्वारा स्थापित उत्तराधिकार के नियम को लंबे उपयोग से अपना बल प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जा सकता है और वादी किसी भी स्थिति में सफल होने का हकदार नहीं था।

उनके अधिपत्यों ने सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित किया जो प्रथागत कानून के प्रश्नों से निपटने में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

(1) यह माना जाना चाहिए कि पंजाब में कई कृषि जनजातियां विभिन्न रीति-रिवाजों द्वारा शासित हैं, जो पंजाब कानून अधिनियम, 1872 की धारा 5 में उल्लिखित विरासत और अन्य मामलों के संबंध में हिंदू और मुस्लिम कानून के सामान्य नियमों से अलग हैं।

(2) सिर्फ इतना ही अच्छा है, यह कोई धारणा नहीं है कि किसी भी देश की आवश्यकता क्या है और यह देश की आवश्यकता के अनुरूप है। (1906) 390,410 पर देखे; अब्दुल हुसैन खान बनम बनम बीबी सोना देरो, एल। 45 आई. ए. 10)

(3) बाध्यकारी होने के लिए, एक प्रथा को इस तथ्य से अपना बल प्राप्त करना चाहिए कि लंबे समय तक उपयोग करने से उसने कानून का बल प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंग्रेजी नियम है कि "एक प्रथा, ताकि यह कानूनी और बाध्यकारी हो, का उपयोग लंबे समय से किया जाना चाहिए कि मनुष्य की स्मृति इसके विपरीत नहीं है" भारतीय स्थितियों पर सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह साबित करने के लिए केवल इतना आवश्यक है कि उपयोग को इतनी लंबी अवधि के लिए और इस तरह की अपरिवर्तनीयता के साथ व्यवहार में लागू किया गया है कि यह दिखाने के लिए कि इसे सहमति पर, किसी विशेष इलाके के स्थापित शासी नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। (देखें माउंट सुभानी बनाम नवाब, ए. एल. आर. 1941 पी. सी. 21 32)।

(4) एक प्रथा को जनजाति या परिवार के सदस्यों द्वारा उसके अस्तित्व के लिए सामान्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से इसके अस्तित्व और बिना किसी विवाद के इसके अभ्यास से अवगत होंगे, और इस तरह के साक्ष्य पर तब सुरक्षित रूप से कार्रवाई की जा सकती है जब वह होः रिवाज के सार्वजनिक रिकॉर्ड जैसे कि रिवाज-ए-आम, या प्रथागत कानून की नियमावली द्वारा समर्थित। (अहमद खान बनाम माउंट देखें। चन्नी बीबी, ए. एल. आर. 1925 पी. सी. 267 पर 271)।

(5) कोई वैधानिक अनुमान रिवाज-ए-आम की सामग्री या इसी तरह के संकलन से जुड़ा नहीं है, लेकिन सरकारी नियमों के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया एक सार्वजनिक रिकॉर्ड होने के नाते, प्रथा के समर्थन में पाए जाने वाले बयान उसमें पढ़े गए तथ्यों को साबित करने के लिए स्वीकार्य हैं और 'आम तौर पर सीमा शुल्क का एक मजबूत सबूत माना जाएगा' हालांकि रिवाज-ए-आम में प्रविष्टियां गलत साबित हो सकती हैं, और उनका खंडन करने के उद्देश्य से आवश्यक सबूत की मात्रा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगी। रियाज-ए-आम से जुड़ी शुद्धता की धारणा का खंडन किया जा सकता है, अगर यह दिखाया जाता है कि यह महिलाओं या किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिनके पास राजस्व अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का कोई अवसर नहीं था। (सेक बेग बनाम अल्लाह डिट्टा, ए. एल. आर. 1916 पी. सी. 129 131 पर; सालेह मोहम्मद बनाम ज़ावर हुसैन, ए. एल. आर. 1944 पी. सी. 18; माउंट। सुभानी बनाम नवाब ए. एल. आर. 1941 पी. सी. 21 पर 25)।

(6) जब एक कृषक पर लागू होने वाली प्रथा का सवाल उठाया जाता है, तो यह उस पक्ष के लिए खुला है जो प्रथा के अनुप्रयोग से इनकार करता है कि जो व्यक्ति इसके द्वारा शासित होने का दावा करता है वह पूरी तरह से और स्थायी रूप से कृषि और

कृषि संघों से दूर चला गया है और शहरी जीवन में अच्छे के लिए बस गया है और व्यापार, सेवा आदि को अपने प्रमुख व्यवसाय और साधन और आजीविका के स्रोत के रूप में अपनाया है, और कृषकों पर लागू होने वाले अन्य रीति-रिवाजों का पालन नहीं करता है। (देखें मुहम्मद हयात खान बनाम संधे खान और अन्य, 55 पी. आर. (1906) 270 पर 274; मुजफ्फर मुहम्मद बनाम इमाम दीन, आई. एल. आर. (1928) 9 लाह। 120, 125)।

(7) किसी आई. डी. 1 के संकलक या निपटान अधिकारी द्वारा विषय के बारे में अपने अंतरंग ज्ञान और जांच के परिणामस्वरूप व्यक्त की गई राय को महत्व दिया जाता है जो प्रत्येक मामले के संदर्भों के अनुसार अलग-अलग होगी। संकलक की टिप्पणियों के साथ जुड़े वजन के संबंध में एकमात्र सुरक्षित नियम यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि यदि वे उसकी व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और लंबे समय से चली आ रही प्रथा के रिकॉर्ड से हट जाते हैं, तो वे प्रथा को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन यदि वे प्रथा की प्रयोज्यता के दायरे और किसी भी विशेष अर्थ के बारे में उनकी जांच और जांच का परिणाम हैं जिसमें प्रथा के प्रतिपादकों ने इसके संबंध में खुद को व्यक्त किया है, तो ऐसी टिप्पणियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। (देखें नारायण सिंह बनाम माउंट। बसंत कौर, ए. आई. आर. 1935 लाहौर 419 421, 422 पर; माउंट. चिंटो बनाम थेलर, ए. आई. आर. 1935 लाहौर 985; खेदम हुसैन बनाम मोहम्मद बनाम हुसैन, ए. आई. आर. 1941 लाहौर 73 पर 79

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1951 का 158

वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, कांगड़ा की अदालत के 25 नवंबर, 1944 के फैसले और डिक्री से उत्पन्न होने वाली 1945 की नियमित पहली अपील संख्या 133 में में

पंजाब उच्च न्यायालय, शिमला (तेजा सिंह और खोसला जे.) के 24 मार्च, 1948 के फैसले और डिक्री से अपील।

अपीलार्थी के लिए दरियादत्ता चावला।

प्रतिवादी के लिए गुरबचन सिंह (जिंद्र लाल, उनके साथ)।

16 मई, 1952. अदालत का निर्णय एफ. ए. जेड. एल. अली द्वारा दिया गया था, जो शिमला में पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री के खिलाफ एक अपील है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा इस घोषणा के लिए दायर एक मुकदमे में कांगड़ा के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले और डिक्री को उलट दिया गया है कि वह एक मुसम्मत राम प्यारी का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी था, जिस पर उसने अपनी पत्नी होने का आरोप लगाया था, और 1 के रूप में वह उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों और उन संपत्तियों के कब्जे का हकदार था। 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, अर्थात्। परवीन कुमारी, जिन पर राम प्यारी द्वारा वादी की बेटी होने का आरोप लगाया गया था, और श्रीमती राज कुमारी, जिन्हें क्रमशः बचाव पक्ष-1 और 2 के रूप में शामिल किया गया था।

वादी का मामला जैसा कि शिकायत में निर्धारित किया गया थाः कि उसका विवाह राज कुमारी (प्रतिवादी संख्या 2) के एक कर्मचारी की बेटी राम प्यारी से हुआ था, जो मुकदमा शुरू होने से लगभग 22 साल पहले थी, कि शादी के बाद वह उसके साथ होशियारपुर में रहती थी और उसने एक बेटी, परवीन कुमारी (प्रतिवादी संख्या 1) को जन्म दिया, 4 मार्च, 1929 को, और राम प्यारी की अप्रैल, 1941 में मृत्यु हो गई, जिसमें चल और अचल दोनों संपत्तियां रह गईं जो उसने अपने पैसे की सहायता से अपने नाम पर अर्जित की थीं और जिन्हें राज कुमारी ने अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वह होशियारपुर जिले की तहसील गढ़शंकर से संबंधित

जाति से राजपूत थे, और उत्तराधिकार के मामलों में प्रथा द्वारा शासित थे, और उस प्रथा के अनुसार, मृतक राम प्यारी के पति के रूप में, वह अपनी बेटी परवीन कुमारी को छोड़कर उनके द्वारा छोड़ी गई चल और अचल संपत्तियों के हकदार थे।

परवीन कुमारी और राज कुमारी दोनों ने इस मुकदमे का विरोध किया और दोनों ने इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी का विवाह राम प्यारी से हुआ था। उनका मामला यह था कि मुकदमे में संपत्तियों का अधिग्रहण राज कुमारी ने राम प्यारी के लिए अपने पैसे से किया था, कि बाद वाले ने अपनी बेटी, परवीन कुमारी को वसीयत की थी, कि अपीलकर्ता प्रथा द्वारा शासित नहीं था, और यह कि किसी भी घटना में कथित प्रथा राम प्यारी की व्यक्तिगत और स्व-अधिग्रहित संपत्ति पर लागू नहीं हो सकती थी। शिकायत में दावा की गई संपत्तियों की सूची में शामिल 2 कारों के संबंध में, राज कुमारी का मामला यह था कि वे उनकी थीं और मृतक केवल एक बेनामीदार थी।

निचली अदालत ने राज कुमारी की 2 कारों को छोड़कर सभी संपत्तियों के संबंध में वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि राम प्यारी अपीलार्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, कि वह पारंपरिक कानून द्वारा शासित था जो राजपूतों के लिए लागू होता था. होशियारपुर जिले के उत्तराधिकार के मामलों के लिए, और उस प्रथागत कानून के अनुसार वह राम प्यारी की संपत्ति के लिए तरजीही उत्तराधिकारी था. अदालत ने आगे कहा कि राम प्यारी की वसीयत अमान्य थी क्योंकि उसके पास वसीयत बनाने के लिए प्रथागत कानून के तहत कोई शक्ति नहीं थी।

दोनों प्रतिवादियों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की, और अपील को अंततः स्वीकार कर लिया गया और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालाँकि वादी और

राम प्यारी के लंबे समय तक रहने के साक्ष्य थे, अर्थात विवाह की धारणा के लिए, फिर भी इस धारणा का पूरी तरह से खंडन किया गया था। और अभिलेख पर साक्ष्य पर पहुंचने के लिए उचित निष्कर्ष यह था कि वादी यह साबित करने में सक्षम नहीं था कि राम प्यारी उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। प्रथा के अनुसार, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार थेः -

1) कि अपीलार्थी होशियारपुर जिले की एक कृषि जनजाति से संबंधित था और इसलिए उस जिले के राजपूतों के बीच प्रचलित प्रथा द्वारा शासित था;

2) यह कि कोई स्थानीय या सामान्य प्रथा नहीं थी जो वादी को राम प्यारी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, जो उसे एक अजनबी, राज कुमारी द्वारा दी गई थी, पर बेटी को वरीयता देने में सफल होने की अनुमति देती थी; और

3) कि पक्ष हिंदू कानून द्वारा शासित थे जिसके तहत राम प्यारी की बेटी होने के नाते परवीन कुमारी को वादी की वरीयता में राम प्यारी द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार था।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, वादी ने अब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 के तहत उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद इस उपस्थिति को प्राथमिकता दी है।

इस अपील में जो पहला सवाल उठता है वह यह है कि क्या वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि राम प्यारी उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। वादी होशियारपुर में जिला न्यायाधीश की अदालत में एक प्रतिलिपिकार के रूप में कार्यरत था और उस शहर में रह रहा था। उसका मामला यह था कि वह कांगड़ा जिले की एक धनी महिला राज कुमारी (प्रतिवादी संख्या 2) से परिचित हो गया, जो तहसील पालमपुर में एक चाय की जागीर का मालिक था और कभी-कभी होशियारपुर जाता था,

और उसके अच्छे कार्यालयों के माध्यम से राम प्यारी से शादी की गई, जो एक लड़की की बेटी थी जो अपनी चाय की जागीर में काम करने वाली राज कुमारी के कर्मचारी चंदर बीर की बेटी थी। शादी के बाद, राम प्यारी अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में होशियारपुर में सादे व्यक्ति के साथ रहते हैं, और 4 मार्च, 1929 को उनके घर पर एक बेटी, परवीन कुमारी (जिसे उषा रानी भी कहा जाता है) का जन्म हुआ। राज कुमारी को राम प्यारी के प्रति बहुत लगाव था और वह अक्सर उनसे मिलने के लिए होशियारपुर जाती थीं। वर्ष 1934-35 में (शिकायत में कोई तारीख का उल्लेख नहीं है; लेकिन इस साल वादी के साक्ष्य में उल्लेख किया गया है), राज कुमारी राम प्यारी को मनोरंजन के लिए बाहर ले जाने के बहाने हर विवरण के सामान के साथ वादी के घर से ले गई। राम प्यारी को राज कुमारी के साथ घूमना पसंद नहीं था और हालांकि वह वादी के पास वापस आना चाहती थी, लेकिन उनमें राज कुमारी की अवज्ञा करने का साहस नहीं था, और वास्तव में राम प्यारी और राज कुमारी अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान एक-दूसरे से नफरत करते थे। वर्ष 1941 में, राम प्यारी की लाहौर के मेयो अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिससे उन संपत्तियों को विवाद में छोड़ दिया गया जिन्हें उसने वादी के अपने पैसे से अच्छे प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित किया था।

वादी के इस कथन के विपरीत, राज कुमारी का मामला यह था कि राम प्यारी को 1921 में किसी समय एक मोटर चालक द्वारा लुभाया गया था, जिसके साथ वह लगभग 11 साल बाद होल्टा एस्टेट में लौट आई थी। परवीन कुमारी जो तब लगभग 3 साल की थी, और लौटने के बाद वह और उसकी बेटी दोनों उसके (राज कुमारी) साथ तब तक रहीं जब तक कि 1941 में राम प्यारी की मृत्यु नहीं हो गई, राज कुमारी एक विधवा होने के नाते बहुत अकेली महसूस करती थीं और इसलिए उन्होंने राम प्यारी को एक साथी के रूप में पाला और विवादित सभी संपत्तियों को राम प्यारी के लाभ के लिए अपने स्वयं के पैसे से अर्जित कर लिया था। परवीन कुमारी को उसके खर्च पर शिक्षित

और पाला गया था, और यह पूरी तरह से गलत था कि वह और राम प्यारी एक-दूसरे से नफरत करते थे, सच्चाई यह थी कि वे एक-दूसरे को पसंद करते थे और एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

यह साबित करने के लिए कि राम प्यारी उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में आंशिक रूप से कई गवाहों के साक्ष्य और आंशिक रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य शामिल हैं। बाबू राम, पी. डब्ल्यू. 7, अरांत राम, पी. डब्ल्यू. 11, बाबू, पी. डब्ल्यू. 12 और आसा राम द्वारा विवाह का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। पी. डब्ल्यू. 13. बाबू राम पारिवारिक पुजारी होने का दावा करता है और आरोप लगाता है कि उसने वादी की शादी के समय पुजारी के रूप में कार्य किया था। अनंत राम और आसा राम जसवाल राजपूत हैं जो गाँव भाम में रहते हैं, जो प्लाई के पास है, नटीफ का गाँव, अजनोहा, और बाबू एक नाई है। इन चार व्यक्तियों ने कहा है कि वे शादी की पार्टी के साथ थे और राम प्यारी के साथ वादी की शादी उनकी उपस्थिति में मनाई गई थी। अन्य गवाहों के साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिन पर वादी द्वारा भरोसा किया गया है, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अपने फैसले में इन शब्दों में संक्षेपित किया गया हैः -

> "पी. डब्ल्यू. 5 मुखी राम होशियारपुर में नगर आयुक्त हैं। पी. डब्ल्यू. 4 डॉक्टर शादी लाल होशियारपुर के एक प्रमुख चिकित्सक हैं। पी. डब्ल्यू. 9 लाला शाम लाल और पी. डब्ल्यू. 10 लाला हर नारायण उसी कार्यालय में वादी के साथ सह-कर्मचारी रहे हैं। हालाँकि इन व्यक्तियों (पी. डब्ल्यू. 9 को छोड़कर) का वादी और उसके परिवार के साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं है, फिर भी वे राम प्यारी को वादी के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहते हुए देख रहे हैं। उसे वादी द्वारा घोषित किया गया था और दोनों को मोहल्ला के लोगों द्वारा और वादी

के गाँव में भाईचारे द्वारा पति और पत्नी के रूप में माना जाता था। प्रदर्शनी पी-18 और पी-19 से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 1932 में वादी की देखभाल करने वाले राम प्यारी को संबोधित कर रहा है और उसे पत्राचार प्राप्त हो रहा है, वादी की देखभाल जो दर्शाती है कि उसने राम प्यारी के साथ वादी के गठबंधन को मंजूरी दी थी। राम प्यारी का छोटा भाई पारस राम गोकल चंद के घर में रहता था और यह सबूत है कि वह वादी को जीजा के रूप में संबोधित करता था-बहन के पति के लिए एक सामान्य नाम। 1930 से 1934 तक होशियारपुर के डी. ए. वी. हाई स्कूल में पढ़े गए पारस राम और प्रदर्शनी पी. डब्ल्यू. 6/1 से 6 तक स्कूल के रजिस्टरों में प्रविष्टियों की प्रतियां हैं जो वादी गोकल चंद द्वारा अपने वार्ड पारस राम, चंदर बीर के बेटे, जिसे उनके साला (पत्नी का भाई) के रूप में वर्णित किया गया था, के प्रवेश के लिए दिए गए आवेदनों के संबंध में हैं। पी. डब्ल्यू. 6 लाला बिशन दास, शिक्षक ने इन प्रतियों को दाखिल किया है। उसकी बहन का घर वादी के घर के बगल में था और उसे उन वर्षों के दौरान राम प्यारी को जीवित देखने और वादी द्वारा पत्नी के रूप में व्यवहार किए जाने के अवसर मिले थे।"

जिस साक्ष्य का संदर्भ दिया गया है, उस पर निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राम प्यारी अपीलार्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी।

हालाँकि, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने वादी के विवाह में उपस्थित होने का दावा करने वाले 4 गवाहों के साक्ष्य को काफी अविश्वसनीय पाया, और उन्होंने बताया कि वादी का मामला यह है कि उसकी शादी बहुत धूमधाम और प्रदर्शन के साथ की गई थी, यह आश्चर्य की बात है कि इससे संबंधित साक्ष्य 4 व्यक्तियों तक सीमित

होना चाहिए, जिनमें से एक किराए का गवाह प्रतीत होता है और अन्य 3 इच्छुक व्यक्ति थे।

वादी के विवाह में उपस्थित होने का दावा करने वाले 4 व्यक्तियों के साक्ष्य के संबंध में, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। अन्य गवाहों का साक्ष्य निस्संदेह इस तथ्य को स्थापित करता है कि कुछ वर्षों तक वादी और राम प्यारी पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, कि राम प्यारी के भाई पारस राम ने वादी को जीजा (बहन के पति के लिए एक सामान्य नाम) के रूप में संबोधित किया था, और जब वादी को डी. ए. वी. स्कूल में भर्ती कराया गया था तो उसने पारस राम के अभिभावक के रूप में काम किया था और स्कूल रजिस्टर में कुछ प्रविष्टियों में उसे उसके बहनोई के रूप में वर्णित किया गया था। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि कुछ तथ्यों के समक्ष गवाही देने वाले कुछ विवेकपूर्ण साक्ष्य, जिन पर निचली अदालत ने भरोसा किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन नहीं करते थे, पहला इसलिए कि गवाहों के पास वादी और राम प्यारी के बीच संबंधों के विषय पर ज्ञान का कोई विशेष साधन नहीं था, और दूसरा इसलिए कि जो धारा 50 प्रासंगिक बनाई गई थी वह केवल राय नहीं थी, बल्कि उन व्यक्तियों की "आचरण द्वारा व्यक्त" राय थी जिनके परिवार के सदस्य या अन्यथा, विशेष साधन थे। ज्ञान की। हमें ऐसा लगता है कि यह सवाल कि उन विशेष गवाहों का साक्ष्य धारा 50 के तहत कितनी दूर तक प्रासंगिक है, अकादमिक है, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कई वर्षों तक निरंतर सहवास विवाह की धारणा को बढ़ा सकता है।

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी और राम प्यारी कई वर्षों तक जीवित रहे और उनके साथ पति-पत्नी के रूप में व्यवहार किया गया, और इसके विपरीत निष्कर्ष की ओर इशारा करने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में एक धारणा

बनाई गई होगी कि वे कानूनी रूप से विवाहित थे। लेकिन लंबे समय तक रहने से जो अनुमान लगाया जा सकता है, वह खंडन योग्य है, और यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उस धारणा को कमजोर या नष्ट करती हैं, तो अदालत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती है। हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत हैं कि वर्तमान मामले में, ऐसी परिस्थितियां वांछित नहीं हैं, और उनका संचयी प्रभाव इस निष्कर्ष की गारंटी देता है कि वादी राम प्यारी के साथ अपने विवाह के तथ्य को साबित करने में विफल रहा है। सबसे पहले, वादी ने अपने किसी भी निकट संबंधियों जैसे कि अपने भाई, या अजनोहा में रहने वाले संपार्श्विकों, या किसी भी सह-ग्रामीणों की जांच नहीं की है, जिनकी शादी में उपस्थिति उसके द्वारा जांचे गए गवाहों की उपस्थिति की तुलना में कहीं अधिक संभावित होती। उन्होंने होल्टा एस्टेट में या उसके आसपास रहने वाले किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की है, इस तथ्य के बावजूद कि उनका अपना मामला यह है कि शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। नीचे दी गई अदालतों में यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि प्रतिवादी नं। 2 एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वादी के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्थानीय गवाह उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर पूरी तरह से विचार किया है और इंगित किया है कि राज कुमारी ने पालमपुर से संबंधित कई व्यक्तियों के साथ मुकदमा किया था और ऐसे व्यक्ति उसके प्रभाव में नहीं होंगे, और दूसरा यह कि कोई उचित कारण नहीं दिखाया गया है कि राज कुमारी, जिस पर वादी और राम प्यारी के बीच विवाह का आरोप है, को उसके प्रति पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण रवैया क्यों अपनाना चाहिए। फिर, वादी का समर्थन करने के लिए न तो माता-पिता और न ही राम प्यारी के किसी रिश्तेदार से पूछताछ की गई है। दूसरी ओर, राम प्यारी की अपनी माँ, गंगा ने बयान दिया है कि राम प्यारी ने कभी भी वादी से शादी नहीं की थी, और राम प्यारी द्वारा उसकी वसीयत में दिया गया बयान, जो कि एक बहुत ही मूल्यवान सबूत है, उसी प्रभाव का है। यह भी अविश्वसनीय है कि राम

प्यारी को वादी के लिए जो प्यार था, उसके बावजूद उसने उसे छोड़ दिया और राज कुमारी के साथ रहने चली गई, और यह कि लंबे समय तक जब राम प्यारी दूर था, तो वादी को कभी भी उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था या उसके और उसकी कथित बेटी, परवीन कुमारी के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। परवीन कुमारी अपने बयान में कहती हैं कि उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और जब वह विवेक की उम्र तक पहुंच गईं तो उन्होंने खुद को पालमपुर में रहते हुए पाया। वादी का आचरण-अपनी पत्नी और बेटी के प्रति ऐसी पूर्ण उदासीनता दिखाना, जैसा कि उसके साक्ष्य में प्रकट किया गया है, सबसे अस्वाभाविक है, और. उसे उन संपत्तियों से वंचित करने का मुकदमा दायर करने में उसका आचरण कम अस्वाभाविक नहीं है जो उसके हाथों में उसके द्वारा की गई किसी भी चीज़ के कारण नहीं, बल्कि एक अजनबी द्वारा उसके प्रति दिखाई गई उदारता के परिणामस्वरूप आई थीं। वादी का मामला कि विवादित संपत्तियों का अधिग्रहण 'राम' प्यारी द्वारा उसके पैसे की सहायता से किया गया था, पूरी तरह से असत्य है, और दोनों अदालतों द्वारा यह सही पाया गया है कि उन्हें राज कुमारी द्वारा उसके लिए अधिग्रहित किया गया था। वादी के गवाहों ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए अपने साधनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई यह प्रतीत होती है कि उसके पास कुछ कम वेतन के अलावा शायद ही कोई साधन था जो वह अदालत के टाइपिस्ट के रूप में प्राप्त करता था।

अधिवक्ता और राम प्यारी की अपनी माँ सहित कई गवाहों ने बयान दिया है कि राम प्यारी एक चालक के साथ भाग गई थी और कई वर्षों से होल्टा एस्टेट से दूर रही था। यहाँ तक कि अधीनस्थ न्यायाधीश ने भी भागने की कहानी को खारिज नहीं किया है, और हालाँकि इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि वह वादी से कब और कैसे मिली, लेकिन उसके कुछ वर्षों तक उसके साथ रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित नहीं थे। वादी दावा करता है

कि वह उच्च जाति का राजपूत है, और यह हमें असामान्य लगता है कि उसे अपनी ही जनजाति में शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक गोरखा लड़की से शादी करनी चाहिए जो बहुत गरीब माता-पिता से पैदा हुई थी और उस जगह से दूर थी जहाँ वह खुद रहता था।

तथ्य यह है कि पारस राम कुछ समय तक वादी के साथ रहे और बाद वाले को जिजा के रूप में संबोधित किया, और यह कि वादी ने खुद को पारस राम के संरक्षक और बहनोई के रूप में वर्णित किया, वादी के बचाव पक्ष के संस्करण के अनुरूप है। अगर पारस राम के माता-पिता समृद्ध परिस्थितियों में होते ताकि उन्हें बनाए रखा जा सके और शिक्षित किया जा सके, तो मामला अलग होता, लेकिन यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि-चंदर बीर बहुत गरीब था और उसकी पत्नी और बेटी दोनों को अपनी आजीविका कमाने के लिए राज कुमारी के नौकर के रूप में काम करना पड़ता था।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को वादी द्वारा गलत नहीं दिखाया गया है, और जो भी सही तथ्य हों, हम यह मानने के लिए मजबूर हैं कि साक्ष्य की वर्तमान स्थिति में वादी यह स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है कि राम प्यारी उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी।

जिस दृष्टिकोण से हमने लिया है, उस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या विवादित संपत्तियों का उत्तराधिकार हिंदू कानून द्वारा प्रथागत कानून द्वारा शासित होगा, लेकिन चूंकि हमारे सामने बहुत विस्तार से बहस की गई थी, इसलिए हम सोचते हैं कि हम पक्षों की दलीलों और उन कठिनाइयों को बता सकते हैं जो हमारी राय में हमारे सामने सामग्री पर उन विवादों से निपटने में उत्पन्न होती हैं। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, हम कुछ सामान्य सिद्धांतों को संक्षेप में निर्धारित करना चाहते हैं

जिन्हें हम मानते हैं कि प्रथागत कानून के प्रश्नों से निपटने में ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः -

1) यह माना जाना चाहिए कि पंजाब में कई कृषि जनजातियाँ विभिन्न रीति-रिवाजों द्वारा शासित हैं, जो पंजाब कानून अधिनियम, 1872 की धारा 5 में उल्लिखित विरासत और अन्य मामलों के संबंध में हिंदू और मुस्लिम कानून के सामान्य नियमों से अलग हैं।

2) उपरोक्त तथ्य के बावजूद, यह कोई धारणा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग प्रथा द्वारा शासित है, और एक पक्ष जिसे प्रथागत कानून द्वारा शासित होने का आरोप लगाया जाता है, उसे यह साबित करना होगा कि वह इस तरह से शासित है और उसे अपने द्वारा स्थापित प्रथा के अस्तित्व को भी साबित करना होगा। दया राम बनाम साहेल सिंह और अन्य ('), अब्दुल हुसैन खान बनाम बीबी सना डेरो (2) देखें।

3) बाध्यकारी होने के लिए, एक प्रथा को इस तथ्य से अपना बल प्राप्त करना चाहिए कि लंबे समय तक उपयोग करने से उसने कानून का बल प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंग्रेजी नियम है कि "एक प्रथा, ताकि यह कानूनी और बाध्यकारी हो, का उपयोग इतने लंबे समय तक किया गया होगा कि मनुष्य की स्मृति इसके विपरीत न हो" भारतीय स्थितियों पर सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह साबित करना आवश्यक है कि उपयोग को व्यवहार में इतनी लंबी अवधि के लिए और इतनी अपरिवर्तनीयता के साथ किया गया है कि यह दिखाने के लिए कि इसे आम सहमति से, किसी विशेष इलाके के स्थापित शासी नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।देखें माउंट सुभानी बनाम नवाब (3)।

4) एक प्रथा को जनजाति या परिवार के सदस्यों द्वारा इसके अस्तित्व के बारे में सामान्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से इसके अस्तित्व और बिना किसी विवाद के इसके अभ्यास से अवगत होंगे, और इस तरह के साक्ष्य पर वह सुरक्षित रूप से कार्रवाई कर सकता है जब इसे प्रथा के सार्वजनिक रिकॉर्ड जैसे कि रिवाज-ए-एम या प्रथागत कानून की नियमावली द्वारा समर्थित किया जाता है। अहमद खान बनाम माउंट चन्नी बीबी (')।

5) रियाज-ए-आम या इसी तरह के संकलन की सामग्री से जुड़ा कोई वैधानिक अनुमान नहीं है, लेकिन सरकारी नियमों के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक लोक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया एक सार्वजनिक रिकॉर्ड होने के कारण, प्रथा के समर्थन में पाए जाने वाले बयान उसमें पढ़े गए तथ्यों को साबित करने के लिए स्वीकार्य हैं और आम तौर पर प्रथा का एक मजबूत प्रमाण माना जाएगा। हालाँकि, रिज-ए-आम में प्रविष्टियाँ गलत साबित हो सकती हैं, और उनका खंडन करने के उद्देश्य से आवश्यक साक्ष्य की मात्रा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगी। रियाज-ए-आम से जुड़ी शुद्धता की धारणा का खंडन किया जा सकता है, अगर यह दिखाया जाता है कि यह महिलाओं या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिनके पास राजस्व अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का कोई अवसर नहीं था। बेग बनाम अल्लाह डिट्टा ('), एस देखें।

6) जब एक कृषक पर लागू होने वाली प्रथा का सवाल उठाया जाता है, तो यह उस पक्ष के लिए खुला है जो प्रथा के अनुप्रयोग से इनकार करता है कि जो व्यक्ति इसके द्वारा शासित होने का दावा करता है वह पूरी तरह से और स्थायी रूप से कृषि और कृषि संघों से दूर चला गया है और शहरी जीवन में अच्छे के लिए बस गया है और व्यापार, सेवा आदि को अपने प्रमुख व्यवसाय और साधन और आजीविका के स्रोत के रूप में अपनाया है, और कृषकों पर लागू होने वाले अन्य रीति-रिवाजों का पालन नहीं

करता है। मुहम्मद हयात खान बनाम संधे खान और अन्य (3), मुजफ्फर मुहम्मद बनाम इमाम दीन (4) देखें।

7) रियाज-ए-आम या निपटान अधिकारी के संकलक द्वारा विषय के बारे में अपने अंतरंग ज्ञान और जांच के परिणामस्वरूप व्यक्त की गई राय को महत्व देने का अधिकार है जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगी। संकलक की टिप्पणियों के साथ जुड़े वजन के संबंध में निर्धारित किया जाने वाला एकमात्र सुरक्षित नियम यह है कि यदि वे उसकी व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और लंबे समय से चली आ रही प्रथा के रिकॉर्ड से हट जाते हैं, तो वे प्रथा को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन यदि वे प्रथा की प्रयोज्यता के दायरे और किसी भी विशेष भावना के बारे में उसकी जांच और जांच का परिणाम हैं जिसमें प्रथा के प्रतिपादकों ने इसके संबंध में खुद को व्यक्त किया है, तो ऐसी टिप्पणियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। नारायण सिंह बनाम माउंट। बसंत कौर (5), माउंट चिंटो बनाम थेलूर (6); खेदम हुसैन बनाम मोहम्मद हुसैन (')।

इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वादी के मामले में जो कठिनाई हमें प्रतीत होती है, उसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, वादी के मामले का आधार यह है कि जिस प्रथा के द्वारा वह शासित होने का दावा करता है वह एक "जमींदार प्रथा" है और वह कृषकों के परिवार से संबंधित होने के कारण इसके द्वारा शासित होता है। हालाँकि, सबूतों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने उस गाँव में अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी थी, जिसमें वे थे, कि उनके पूर्वज बैंकर या साहूकार थे, कि उनके पिता होशियारपुर जिले में वकालत करने वाले एक वकील के क्लर्क थे और वे खुद होशियारपुर में जिला न्यायाधीश की अदालत में क्लर्क थे और वहाँ रहते थे, और यह दिखाने के लिए शायद ही कोई सबूत है कि उनके किसी भी रिश्तेदार का कृषि पर निर्भर होना या उनके साथ संबंध था। हमारी राय में, वादी के गवाहों ने उसके आर्थिक

साधनों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है और एक सही तस्वीर नहीं दी है जिस पर इस सवाल का जवाब निर्भर करता है कि क्या वह अभी भी पुरानी प्रथा द्वारा शासित होगा। फिर भी, हालांकि होशियारपुर जिले के रियाज-ए-आम में प्रश्न 11 के उत्तर के अनुसार, उस जिले के राजपूतों को नियंत्रित करने वाली सामान्य प्रथा यह प्रतीत होती है कि केवल जनजाति के भीतर विवाह वैध है, वादी ने अपने जिले के राजपूत से शादी नहीं की थी, बल्कि कहा जाता है कि उसने एक गोरखा महिला से शादी की थी, जिसकी जाति और चरित्र के बारे में सबूत परस्पर विरोधी हैं, और जिसका परिवार स्वीकार्य रूप से "रियाज-ए-आम" द्वारा शासित नहीं था, जिस पर वादी निर्भर करता है। यदि पति और पत्नी दोनों को एक ही जनजाति से संबंधित दिखाया जाता है और एक ही प्रथा द्वारा शासित किया जाता है, तो यह तय करने में कठिनाई हो सकती है कि पत्नी की मृत्यु पर पत्नी की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार का नियम क्या होगा। लेकिन अगर यह भी माना जाए कि राम प्यारी ने वादी के साथ कानूनी रूप से शादी की थी, तो यह तय करने के लिए गंभीर सवाल यह होगा कि क्या उत्तराधिकार वह संपत्ति होगी जो राम प्यारी को एक अजनबी से उपहार के रूप में मिली थी और जो उसके अपने अधिकार में थी, अपने पति के परिवार को नियंत्रित करने वाली प्रथा द्वारा शासित होगी, न कि उसके अपने। ऐसा विवाह जिसके बारे में कहा जाता है कि वादी द्वारा अनुबंधित किया गया था, स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ घटना होने के कारण, उसके द्वारा स्थापित उत्तराधिकार के नियम को लंबे समय तक उपयोग से अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया है, बाध्यकारी होने के लिए एक प्रथा को इस तथ्य से अपना बल प्राप्त करना चाहिए कि लंबे समय तक उपयोग करने से उसने कानून का बल प्राप्त किया है; और यदि वादी द्वारा लागू उत्तराधिकार के नियम को लागू करने का कोई अवसर कभी नहीं आया है, तो पत्नी द्वारा अपने अधिकार में रखी गई संपत्ति पर, जिस नींव पर प्रथा बढ़ती है, वह अभाव होगा।

जब मामले की आगे जांच की जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वादी न केवल प्रथा पर बल्कि आंशिक रूप से प्रथा पर और आंशिक रूप से हिंदू कानून के शासन पर निर्भर करता है, अर्थात्, जो कानून पति को नियंत्रित करता है वह पत्नी को भी नियंत्रित करेगा। क्या बाद के नियम को वर्तमान जैसे किसी मामले तक बढ़ाया जा सकता है, जो कुछ कठिनाई का सवाल है, जिस पर, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम अपनी राय सुरक्षित रखेंगे। इन परिस्थितियों में, हम प्रथा के मुद्दे को अनिर्णित छोड़ना पसंद करते हैं, और अपने निर्णय को एकमात्र आधार पर आधारित करते हैं, जो अपने आप में अपील को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, कि राम प्यारी के साथ वादी की शादी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुई है।

इसलिए अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में और विशेष रूप से जब से अपीलकर्ता ने एक दरिद्र के रूप में अपील की है, हम निर्देश देते हैं कि पक्ष सभी अदालतों में अपना खर्च खुद उठाएंगे।

अपील खारिज की जाती है।

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ताः एस. डी. सेखड़ी।

प्रत्यर्थी का अभिकर्ताः नौनीत लाल।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक कैलाश पुनिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।